



**सरकारी गजट, उत्तरांचल**  
**उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित**  
**असाधारण**

विधायी परिशिष्ट  
भाग—1, खण्ड (क)  
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई 2003 ई0  
आषाढ, 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन  
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग  
संख्या 272 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003  
देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को दिनांक 08 जुलाई, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 15, सन 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003

{अधिनियम संख्या 15 सन् 2003}

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रायोजित “पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय” नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

#### अध्याय-1

#### प्रारम्भिक

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ | 1 | (1) यह अधिनियम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 कहलायेगा।<br>(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।   |
| परिभाषायें                    | 2 | (1) जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—<br>(क) ‘विद्या परिषद्’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;<br>(ख) ‘व्यवस्थापक मण्डल’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल से है;<br>(ग) ‘कैरियर ऐकेडमी सेन्टर’ का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक सम्वाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;<br>(घ) ‘कुलाधिपति’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;<br>(ङ) ‘संगठक महाविद्यालय’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है; <sup>2</sup><br>(च) ‘तकनीकी शिक्षा परिषद्’ का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;<br>(छ) ‘दूरस्थ शिक्षा पद्धति’ का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई-लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो; <sup>2</sup><br>(ज) ‘कर्मचारी’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;<br>(झ) ‘संकाय’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है;<br>(ञ) ‘वित्त समिति’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;<br>(ट) ‘सरकार’ का तात्पर्य {उत्तराखण्ड} <sup>1</sup> सरकार से है; |

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 06 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ठ) 'हाल' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई से है;
- <sup>3</sup>[(ड) 'हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 210 द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, फेज 3 ओखला नई दिल्ली 110020 में है;]
- (ढ) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (ण) संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप-प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (त) "कुल सचिव" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;
- [(थ) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबंध मंडल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;]<sup>2</sup>
- (द) 'राज्य' का तात्पर्य [उत्तराखण्ड]<sup>1</sup> राज्य से है;
- (ध) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावलियों से है;
- [(न) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हो;]<sup>2</sup>
- (प) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिससे विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
- (फ) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन समर्पित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;
- [(ब) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून से है, जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करेगा;]<sup>2</sup>
- (भ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

## अध्याय-2

### विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3—

- (1) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगी।  
इस आवेदन पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे:—  
(क) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;  
(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 06 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।  
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;
- (घ) संकायों की प्रकृति पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे—भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख—सुविधायें;
- (च) आगामी पांच वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;
- (छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
- (ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
- (झ) आन्तरिक संसाधनों—विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
- (ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्योरा;
- (ट) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;
- (ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति ; तथा
- (ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्राप्ति।

विश्वविद्यालय की  
स्थापना

4. (1) यदि राज्य सरकार आवश्यक ऐसी जांच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं तो हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को स्थायी विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देगी;
- (2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, वह राज्य के भीतर तथा अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेंटरों की स्थापना कर सकेगा।<sup>1</sup>
- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।
- (5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

- (6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. <sup>1</sup>{(1) जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं:—
- (क) मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि और औपचारिक विज्ञान का व्यापक अध्ययन, शिक्षण एवं शोध कार्य की व्यवस्था करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के विनियमों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से ऐसे महाविद्यालय की स्थापना करना जो उपरोक्त (क) से सम्बन्धित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य नियामकों द्वारा नामपद्धति के प्रमाण—पत्र, डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान कर सकें;
- (ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों की अनवरत शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए संघटक केन्द्र की स्थापना।
- (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के अन्तर्गत ऐसी गतिविधियाँ, अध्ययन के क्षेत्र, इन्क्यूबेशन केंद्र (Incubation Center), स्टार्टअप्स (Start ups) जो शैक्षणिक परिषद् समय समय पर अनुसार आवश्यक और प्रासंगिक समझें या सुनिश्चित करें।।
- (2) किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में दिया गया है, अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उनके द्वारा:—
- (क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें वह आवश्यक समझे;
- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) व (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के विद्यालयों में ज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना।}

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी—

- <sup>1</sup>[(क) मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि अध्ययन और औपचारिक विज्ञान तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने—
  - (1) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम किया हो; या
  - (2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के अधीन शोध कार्य किया हो;]
  - (घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताएं प्रदान करना;
  - (ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;
  - (च) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;
  - (छ) धारा (7) में उल्लेखित हाइड्रोकार्बन्स पैट्रोलियम और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
  - (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
  - (झ) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
  - (ञ) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ सदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना;
  - (ट) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए हाल स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
  - (ठ) आवास का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
  - (ड) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;
  - (ढ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
  - (ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
  - (त) <sup>1</sup>[अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों औद्योगिक दक्ष, तकनीकी अधिकारियों, शोध और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;]

- (थ) विश्वविद्यालय या किसी संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए {उत्तराखण्ड} राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;
- (द) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हों;
- (ध) <sup>1</sup>{मानविकी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं टेक्नोलोजी अध्ययन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि अध्ययन और औपचारिक विज्ञान तथा सम्बंधित सभी विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना;}
- (न) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी;
- (प) फिल्म कैसेट, टैप, वीडियो कैसेट, सीडी, वीसीडी और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

- (फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;
- (ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;
- (भ) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुंच होगी 9—

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा [उत्तराखण्ड]<sup>1</sup> के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है :

परन्तु, और यह भी इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किस संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय / प्रत्यायन 10—

विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

### अध्याय—3

#### विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी 11—

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) कुलपति;
- (घ) प्रति-कुलपति;(प्रो-वाइस चांसलर)
- (ङ) संकायाध्यक्ष;
- (च) कुल सचिव;
- (छ) वित्त अधिकारी; और
- (ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाय।



- कुलाध्यक्ष (विजिटर) 12— (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
- (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—
- (क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;
- (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- (4) मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।
- कुलाधिपति 13— (1) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली के तत्वाधान में स्थापित संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम विद्यालय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा। तत्पश्चात् हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली अपने सदस्यों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेगी।
- (2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।
- कुलपति 14— (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात्—
- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव;
- (घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।
- (3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।
- (4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
- (5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

		(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।
		(7) कुलाधिपति को सम्यक् जांच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।
प्रति-कुलपति	15—	प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
संकायाध्यक्ष	16—	संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
कुलसचिव	17—	(1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसे कि विहित की जाए। (2) कुल सचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा। (3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों। (4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
वित्त अधिकारी	18—	वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि विहित किये जायें।
अन्य अधिकारीगण	19—	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय।

#### अध्याय—4 विश्वविद्यालय प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	20—	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :— (क) व्यवस्थापक मण्डल; (ख) प्रबन्धक मण्डल; (ग) विद्या परिषद्; (घ) वित्त समिति; और (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।
-----------------------------	-----	---

व्यवस्थापक मण्डल  
और उसकी  
शक्तियां

21— (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:—

- (अ) कुलाधिपति —अध्यक्ष
- (ब) कुलपति —सदस्य सचिव
- (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव;
- (द) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा नामित पांच सदस्य;
- <sup>1</sup>[(य) मान संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
- (र) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा उद्योग/शोध/शिक्षा के क्षेत्र में नामित तीन प्रख्यात सदस्य;
- (ल) कुलाधिपति द्वारा औद्योगिक जगत के पेशेवर/दक्ष अधिकारियों में से नामित तीन अधिकारी, जिनमें से कम से कम एक नामित आधिकारी तेलों और गैस कम्पनियों से हो।]

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
- (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;
- (च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन; और
- (ज) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22— (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- (अ) कुलपति;
- <sup>2</sup>[(ब) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;]
- (स) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा नामित पांच सदस्य;
- (द) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;
- (य) <sup>2</sup>[कुलाधिपति द्वारा नामित तीन संकायाध्यक्ष/निदेशक;]
- (र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो।

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2018 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

विद्या परिषद्	23—	(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (अ) कुलपति — सभापति (ब) कुल सचिव — सचिव; (स) ऐसे अन्य सदस्य — जैसा परिनियमों में विहित किया जाये। (2) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
वित्त समिति	24—	(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (अ) कुलपति — सभापति; (ब) वित्त अधिकारी; (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव पद से कम न हो; (द) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें। (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख-भाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
अन्य प्राधिकरण	25—	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जो कि विहित किये जायें।
रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	26—	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

## अध्याय—5 परिनियम और नियमावली

परिनियम	27—	इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है— (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य—सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है; (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन; (ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य; (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें; (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया; (छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्पादन और उसकी पुनर्संरचना;
---------	-----	---

- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ट) निशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा {उत्तराखण्ड} के विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा {उत्तराखण्ड} के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क;
- (ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
- (त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (थ) अन्य मामले, जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

- 28— (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

- 29— व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

- 30— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे, अर्थात:-
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
  - (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
  - (ग) उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
  - (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
  - (च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
  - (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
  - (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
  - (झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;
  - (ट) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी	31—	(1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेंगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जोकि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।  (2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।
नियमावली को संशोधित करने की शक्ति	32—	राज्य सरकार के अनुमोदन के अधधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

## अध्याय—6

### प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें	33—	(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।  (2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।  (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।  (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।  (5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।
अपील का अधिकार	34—	विश्वविद्यालय या किसी संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
भविष्य निधियां एवं पेंशन	35—	विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।
विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	36—	यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा; जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
समितियों का गठन	37—	जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	38—	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।
सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	39—	कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
संकमणकालीन उपबन्ध	40—	इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:— (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति-कुलपति यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा; (ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद कार्य करेंगे; (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा; (घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।
स्थायी विन्यास निधि	41—	(1) विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम एक करोड़ रुपये स्थायी विन्यास निधि स्थापित की जायेगी जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता; (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी; (3) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित की जा सकती है। विश्वविद्यालय के समापन के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए कोई धनराशि विन्यास निधि की राशि से अन्तरित नहीं की जा सकती; (4) स्थायी विन्यास निधि की राशि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित कर दिया जायेगा।
सामान्य निधि	42—	(1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्— (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले सभी शुल्क; (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि; (ग) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये सभी अंशदान; और (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।
विकास निधि	43—	(1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात्:—

		(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
		(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
		(ग) हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये सभी अंशदान;
		(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
		(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
	(2)	समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
निधि का अनुरक्षण	44—	धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।
वार्षिक प्रतिवेदन	45—	<p>(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।</p> <p>(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।</p>
लेखा व लेखा परीक्षा	46—	<p>(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीआई0ए0आई0) के सदस्य हों।</p> <p>(3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।</p> <p>(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।</p>
विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	47—	विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से विधिवत रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश, कार्यवाही संकल्प या दस्तावेज के या पूंजी में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।



विश्वविद्यालय विघटन	का 48—	<p>(1) यदि हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।</p> <p>(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।</p>
विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	49—	<p>(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।</p> <p>(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्धन ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।</p>
कठिनाईयों निराकरण	का 50—	<p>(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।</p>

# THE UNIVERSITY OF PETROLEUM AND ENERGY STUDIES ACT, 2003

[Act No. 15 of 2003]

## AN ACT

to establish and incorporate an University in the name of University of petroleum and energy Studies with facilities for education, training and research in the areas of petroleum and Energy studies and related areas sponsored by Hydrocarbons Education & Research Society, registered under Societies Registration Act, 1860 at New Delhi.

It is hereby enacted in the fifty fourth year of the Republic of India as follows:

### CHAPTER -1 Preliminary

- |                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
| Short title and commencement | 1- | (1) This Act may be called the University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003.<br><br>(2) It shall be deemed to have come into force on the date, the notification is issued by the State Government.   |
| Definitions                  | 2- | In this Act, unless the context otherwise requires:--<br><br>(a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;<br>(b) “Board of Governors” means the Board of Governors of the University;<br>(c) “Career Academy Centre” means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of receiving telecast, e-mail, internet, interactive talk back, conduction training, organize lectures, seminars and workshops, advising, counseling or rendering any other assistance required by the students;<br>(d) “Chancellor” means the Chancellor of the University;<br>(e) “Constituent College” means a college or institution within the State maintained by the University; <sup>2</sup><br>(f) “Council for Technical Education” means the All India Council for Technical Education established under section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987;<br>(g) “Distance Education system” means the system of imparting education with in the State through any means of information technology and communication such as multimedia, broadcasting, telecasting online on internet, other interactive methods, e-mail, internet, computer, e-learning, correspondence course or a combination of any two or more of such means; <sup>2</sup><br>(h) “Employee” means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;<br>(i) “Faculty” means faculty of the University;<br>(j) “Finance Committee” means the Finance Committee of the University;<br>(k) “Government” means the Government of [Uttarakhand] <sup>1</sup> ; |

---

1. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 06 of 2010.

2. Subs. by section 3 ibid.

- (l) “Hall” means a unit of residence for students maintained or recognized by the University or a constituent college;
- (m) <sup>3</sup>“Hydrocarbons Education And Research Society” means society registered under Societies Registration Act, 1860 having registered office presently at 210, 2<sup>nd</sup> Floor, Okhla Industrial Estate, Phase III, Okhla, New Delhi 110020;}
- (n) “Prescribed” means prescribed by the statutes;
- (o) “Principal” in relation to a constituent college, means the head of the constituent college, and includes, where there is no principal, the Vice principal or any other person for the time being appointed to act as principal;
- (p) “Registrar” means the Registrar of the University;
- (q) “Regional Centre” means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordination and supervising the work of study centers in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (r) “State” means State of [Uttarakhand]<sup>1</sup> ;
- (s) “Statutes” and “Rules” mean, respectively, the statutes and Rules of the University;
- [(t) “Study Centre” means a centre within the State, established, maintained and recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering such other assistance required by the students;]<sup>2</sup>
- (u) “Teacher” means a professor, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College and includes the principal of constituent college;
- (v) “UGC” means University Grants Commission established under university Grants Commission Act, 1956;
- [(w) “University” means proposed University of Petroleum and Energy Studies established under this Act which shall function within the State of Uttarakhand and shall comply with the orders and guidelines of the University Grants Commission;]<sup>2</sup>
- (x) “Visitor” means the Visitor of the University.

## **CHAPTER -2**

### **The University and its Objects**

Proposal for the establishment of the University

- 3- (1) Hydrocarbons Education and Research Society, New Delhi shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.
- (2) An application containing the proposal to establish a University shall be made to the State Government by the Hydrocarbons Education And Research Society. The proposal shall contain the following particulars, namely:-
- (a) the objects of the University along with the details of the Hydrocarbons Education And Research Society;
  - (b) the extent and status of the University and the availability of land;

---

1. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 06 of 2010.  
 2. Subs. by section 3 ibid.  
 3. Subs. by section 4 of UK Act no 24 of 2018.

- (c) the nature and type of programmes of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;
- (d) the nature of faculties, courses of study and research proposed to be started;
- (e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
- (f) the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
- (g) the item wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
- (h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
- (i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;
- (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee freeship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- (k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the Hydrocarbons Education And Research Society as well as the financial resources;
- (l) the system for selection of students to the courses of study at the University ; and
- (m) status of fulfillment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

Establishment  
of University

- 4- (1) Where the state Government, after such inquiry as it may deem necessary, is satisfied that hydrocarbons Education And Research Society has fulfilled the conditions specified in sub-section (2) of section 3, it may direct the Hydrocarbons Education And Research Society to establish an Endowment Fund.
- (2) After the establishment of the Endowment Fund, the State Government may, by notification in the Official Gazette, accord sanction for establishment of the University.
- [(3) The Headquarters of the University shall be at Dehradun, Uttarakhand and it may also have campuses or regional centers, Study Centers and career Academic Centers at other places in the State, as may be specified from time to time.]<sup>1</sup>
- (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.
- (5) On the establishment of the University under sub-section (2), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University except the properties of

Hydrocarbons Education And Research Society, shall stand transferred to, and vest in, the University.

- 
1. Substituted by section 4 of Uttarakhand Act No. 06 of 2010.

University not to be entitled to financial assistance	5-	(3) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.  The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in –aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.
No power to affiliate any institution	6-	The University may have Constituent Colleges, Regional Centres, Study Centres and Career Academy Centres but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.
Objects or the University	7-	<p>[(1) The objectives for which the University is established are as follows:-</p> <p><b>(a)</b> To provide extensive study, teaching and research in Humanities, Social Science, Natural Science, Engineering Technology, Medical, Dental &amp; Health Science, Law Studies and Formal Science;</p> <p><b>(b)</b> To establish such college under the Regulation of University Grants Commission with prior permission of University Grants Commission and the State Government which may provide Certificate, Diploma, Undergraduation, Post Graduation and Ph.D. Courses related to the abovesaid (a) and of nomenclature by UGC and other Regulatory;</p> <p><b>(c)</b> To establish constituent Center under the Regulation of University Grants Commission with prior permission of University Grants Commission and the State Government for the purpose of continuous education of the courses mentioned in above said (a) and (b) to provide education through distance learning program;</p> <p><b>(d)</b> Such activities or fields of study, incubation centers, startups etc which the Academic council deems or ensure necessary and relevant from time to time under the regulation of University Grants Commission;</p> <p>(2) To establish an R &amp; D center to promote research and innovations in any discipline as in Section 7(1) (a) and (b) above and thereby,</p> <p><b>(a)</b> To provide for instructions and training in such related branches of learning as it may deem fit;</p> <p><b>(b)</b> To provide for research for the advancement and Dissemination of knowledge in the college of any discipline mentioned in clause (a) and (b) of subsection (1) of section (7).]</p>

---

1- Subs. by section 5 of the UK Act no 24 of 2018.

Power of the  
University

8- (1) The University shall have the following powers, viz:---

- (a) <sup>1</sup>[to provide for instructions in all disciplines related to Humanities, Social Science, Natural Science, Engineering, Technology, Medical, Dental & Health Science and Formal Science and to make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge therein;
- (b) to carry out all such activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;
- (c) to hold examinations for, and to institute Grants and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who —
  - (i) have pursued a Program of study in the University or in a constituent College or through its distance education system at regional Center/Study Center/Career Academy Centre; or
  - (ii) have carried on research in the University or in a constituent body.]
- (d) To confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/ provisions;
- (e) To institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;
- (f) to demand and receive such fees, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (g) to make provisions for the advancement of education in Hydrocarbons, petroleum and other areas mentioned in section 7;
- (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;
- (i) to make appointments of faculty, officers and employees of the University or a constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre;
- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a constituent college, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre with the prior permission of Hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi;
- (k) to institute and maintain halls and to recognize places of residence for students or the University or in a Constituent College;
- (l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their code of conduct;
- (m) to create administrative, managerial, employees and other necessary posts;
- (n) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;

- (p) <sup>1</sup>[to organize and conduct courses, orientation courses, workshops, seminars and other programs for industry professionals, teachers, lesson writers, evaluators, research staff, academic staff, technical officers, students;]
- (q) to determine standards of admission to the University or a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre through specialized committees with the approval of Academic Council;
- (r) to make special provision for students belonging to the state of Uttarakhand for admission in any course of the University or in a constituent college, regional center, study centre and career academy centre;
- (s) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
- (t) <sup>1</sup>[to prescribe such course for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start diplomas and certificates, etc in Humanities, Social Science, Natural Science, Engineering, Technology, Medical, Dental & Health Science, Legal Studies and Formal Science and related subjects;]
- (u) to clearly set apart Academic Activities of the University from the activities the society;

---

1- Subs. by section 6 of UK Act no 24 of 2018.



- (v) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, CD,VCD and other software's;
  - (w) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full of in part) at, other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
  - (x) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval of the Governing Body whether on the security of the University, money for the purpose of the University;
  - (y) to enter into, carry out , vary or cancel contracts.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the open university and distance education systems and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems, and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to colleges, Regional Centres and Study Centres whether admitted to its privileges or not, or to any other University or institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.

University  
open to all  
classes, castes,  
creed and  
gender

9-

The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or gender :--

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission to students of the State of [Uttarakhand] :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to requires the University or constituent colleges or Regional Centres or Study Centres or Career Academy Centres to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the statutes.

National  
Accreditation

10-

The University will seek accreditation from the national University accreditation body.

### **CHAPTER-III** **Officers of the University**

Officers of the  
University

11-

The following shall be the officers of the University:--

- (a) the Visitor;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;
- (d) the pro Vice-Chancellor;
- (e) the deans of faculties;
- (f) the Registrar;
- (g) the finance officer; and
- (h) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| The Visitor         | <p>12- (1) The Governor of Uttarakhand will be the Visitor of the University.</p> <p>(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.</p> <p>(3) The Visitor shall have the following powers namely:--</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) to call for any paper or information relating to the affairs of the University.</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned.</p> <p>(4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.</p>   |
| The Chancellor      | <p>13- (1) Chairman of Board of Studies of Indian School of Petroleum an institute under the aegis of Hydrocarbons Education &amp; Research society will be the first Chancellor of the University of Petroleum And Energy Studies, whose tenure shall be of three years. Thereafter the Hydrocarbons Education And Research Society, with the prior concurrence of the Visitor, would appoint Chancellor from amongst its members.</p> <p>(2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.</p>   |
| The Vice-Chancellor | <p>14- (1) The Vice-chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).</p> <p>(2) The committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, viz,:-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) One person nominated by the Visitor;</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) One person nominated by the Chancellor;</p> <p style="padding-left: 40px;">(c) The principal secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department;</p> <p style="padding-left: 40px;">(d) Three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the Governor of the committee by the Board of Governors.</p> <p>(3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.</p> <p>(4) The Vice-chancellor shall be the principal Executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.</p> <p>(5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.</p> |

		(6) The Vice-chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the statutes or the Rules.
		(7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the chancellor to suspend the Vice- Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
The Pro-Vice-Chancellor	15-	A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
Deans of faculties	16-	Deans of faculties shall be appointed by the Vice-chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
The Registrar	17-	(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University. (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor. (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and document as may be necessary for transaction of their business.
The Finance Officer	18-	The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
Other Officers	19-	The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

#### **CHAPTER –IV**

##### **Authorities of the University**

Authorities of the University	20-	The following shall be the authorities of the University, namely:--- (a) The Board of Governors; (b) The Board of management; (c) The Academic Council; (d) The Finance committee; and (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
The Board of Governors and its powers	21-	(1) The Board of Governors shall consist of: (a) The Chancellor ---Chairman; (b) The Vice-Chancellor -Member-Secretary; (c) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department or a Secretary to the State Government nominated

- by the State Government;
- (d) Five persons nominated by the hydrocarbons Education and Research Society, New Delhi;
  - (e) <sup>1</sup>[A Nominee Officer from Institution of National Importance (as maintained by MHRD, Government of India), nominated by the Chancellor;;
  - (f) Three Eminent Persons from Industry/Research/Academics nominated by the Visitor;
  - (g) Three nominee officers from the Professionals/ Experts of the Industrial world, nominated by the Chancellor including at least one nominated officer from the Oil & Gas companies.]
- (2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely;--
- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
  - (b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
  - (c) to approve the budget and annual report of the University;
  - (d) to make new or additional statutes or amend or repeal the earlier statutes and Rules;
  - (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
  - (f) to approve proposals for submission to the State Government; and
  - (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.
- (3) The Board of Governors shall, meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.
- The Board 22-  
management
- (1) The Board of management shall consist of:--
- (a) The Vice-Chancellor;
  - (b) <sup>2</sup>[A Nominee from Institutions of National Importance (as maintained by MHRD Government of India) nominated by the Chancellor;]
  - (c) Five persons, nominated by the hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi;
  - (d) Two professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;
  - (e) <sup>2</sup>[Three Deans/ Directors of the Faculties as nominated by the Chancellor;]
  - (f) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of management.
- (2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

---

1. Subs. by section 7 of UK Act no 24 of 2018.

2. Subs. by section 8 of UK Act no 24 of 2018.

The Academic Council	23-	<p>(1) The Academic Council shall consist of:--</p> <p>(a) the Vice-Chancellor-Chairman;</p> <p>(b) the Registrar- Secretary;</p> <p>(c) such other members as may be prescribed in the Statutes.</p> <p>(2) The Academic Council shall be the principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the statutes and the Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.</p>
The Finance committee	24-	<p>(1) The finance committee shall consist of :-</p> <p>(a) the Vice Chancellor-Chairman;</p> <p>(b) the finance Officer;</p> <p>(c) principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department of his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;</p> <p>(d) Such other members as may be prescribed in the Statutes.</p> <p>(2) The finance committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.</p>
Other Authorities	25-	The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.
Proceedings not invalidated on account of Vacancy	26-	No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

## **CHAPTER-V**

### **Statutes and Rules**

Statutes	27-	<p>Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as given below:-</p> <p>(a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;</p> <p>(b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;</p> <p>(c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;</p> <p>(d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;</p> <p>(e) the procedure for resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;</p> <p>(f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;</p> <p>(g) the manner of co-operation with other Universities or Institutions of higher</p>
----------	-----	---

		learning;
		(h) the procedure for conferment of honorary degrees;
		(i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
		(j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for [Uttarakhand] students;
		(k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
		(l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
		(m) procedure for creation and abolition of posts;
		(n) other matters, which may be prescribed.
Statutes how made	28-	<p>(1) The first statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.</p> <p>(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under sub-section (1) it shall be deemed to have been approved by the State Government.</p>
Power to amend the Statutes	29-	The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.
Rules	30-	<p>Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely-----</p> <p>(a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;</p> <p>(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;</p> <p>(c) the award of degrees and other academic distinctions;</p> <p>(d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;</p> <p>(e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;</p> <p>(f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;</p> <p>(g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;</p> <p>(h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;</p> <p>(i) all other matters as may be provided in the statutes and Rules under the Act.</p>

Rules how made	31-	(1) The rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.  (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.
Power to amend Rules	32-	The Board of Governors may, with the approval of the State Government make new or additional rules or amend or repeal the rules.

## **CHAPTER-VI**

### **Miscellaneous**

Conditions service of employees	33-	(1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned. (2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes. (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor. (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final. (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.
Right to appeal	34-	Every employee or student of the University or of a constituent college, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre shall, notwithstanding anything contained in the proposed Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the principal of any such Constituent college, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre college, as the case may be and thereupon the Board of management may confirm, modify or change the decision appealed against.
Provident fund and pension	35-	The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
Disputes as to constitution of University authorities and bodies	36-	If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
Constitution of committees	37-	Whenever any authority of the University is given power by this Act or the statutes to appoint committees, such committees, shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of

such other persons, if any, as the authority in each case thinks fit.

Filling of casual vacancies	38-	Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.
Protection of action taken in good faith	39-	No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules.
Transitional provisions	40-	<p>Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act and the Statutes:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) the first Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three year;</li><li>(b) the first Registrar and the first Finance officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;</li><li>(c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;</li><li>(d) the first Board of management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.</li></ul>
Permanent Endowment Fund	41-	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees one crore which may be increased suo motu but shall not be decreased.</li><li>(2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.</li><li>(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund for other purposes.</li><li>(4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund shall be used for the purposes of development works of the University. The remaining 25% shall be reinvested into the permanent endowment fund.</li></ul>
General Fund	42-	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-<ul style="list-style-type: none"><li>(a) all fees which may be charged by the University;</li><li>(b) all sums received from any other source;</li><li>(c) all contributions made by the Hydrocarbon Education and Research Society, new Delhi;</li><li>(d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.</li></ul></li><li>(2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the university.</li></ul>



Development fund	43-	<p>(1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) development fees which may be charged from students;</li> <li>(b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;</li> <li>(c) all contributions made by the hydrocarbons Education &amp; Research Society;</li> <li>(d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and</li> <li>(e) all incomes received from the permanent endowment fund.</li> </ul> <p>(2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.</p>
Maintenance of fund	44-	The funds established under section 41, 42 and 43 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.
Annual Report	45-	<p>(1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.</p> <p>(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.</p> <p>(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.</p>
Account and Audit	46-	<p>(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.</p> <p>(2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.</p> <p>(3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.</p> <p>(4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observations thereon before the 31<sup>st</sup> December each year.</p> <p>(5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.</p>
Mode of proof of University record	47-	A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the university or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or

Dissolution of University	<p>document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.</p> <p>48- (1) If Hydrocarbons Education &amp; Research society, New Delhi proposes dissolution of the University of Petroleum and Energy Studies in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.</p> <p>(2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.</p> <p>(3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the hydrocarbons Education &amp; Research society.</p> <p>(4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the Council for Technical Education and UGC make such arrangements for administration of the University from date of dissolution of the University by Hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the statutes.</p>
Expenditure of the University during dissolution	<p>49- (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 48 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.</p> <p>(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.</p>
Removal of difficulties	<p>50- (1) If any difficulty arises in giving effect of the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty;</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that no notifications order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.</p> <p>(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.</p>